

प्रेषक,  
मनीषा पंवार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून 2 अक्टूबर 2008.

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1441/स.क./लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2008-09, दिनांक 02 जुलाई 2008 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए शासनादेश संख्या-389/XVII-1/2008-10(19)/2007, दिनांक 01 मई 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 39,000/- (रुपये उनचालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों तथा मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की "अनुदान संख्या-15" के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-001-निर्देशन तथा प्रशासन-05-जिला कार्यालयों का अधिष्ठान-00" की मानक मद "16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न प्रारूप "बी.एम.-15" के "पुनर्विनियोजन कालम-01" की बचतों से वहन किया जाएगा।
8. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-294(NP)/XXVII(3)/2008, दिनांक 10 अक्टूबर 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

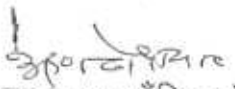
  
(मनीषा पंवार)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 973 (1)/XVII-1/2008-10(19)/2007, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

  
(अरुण कुमार ढोंडियाल)  
अपर सचिव।